नवभारत 3-11-2023 पृ.क्र.5 (८)

तकनीक | फसल ऋण की प्रक्रिया आसान करने का उद्देश्य

12 हजार संस्थाएं होंगी कम्प्यूटरीकृत

20 हजार से ज्यादा संस्थाएं देती हैं कर्ज

■ **पुणे, ब्यूरो.** किसानों को समय पर फसल ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि ऋण प्रदान करने वाले सभी विभिन्न कार्यकारी सेवा संगठनों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा. इसमें पहले चरण में 12 हजार संस्थानों का चयन किया गया है और अब तक 4 हजार 500 संस्थानों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसे तीन से पांच साल का समय लगेगा. यह जानकारी सहकारिता आयुक्त अनिल कवड़े ने दी. वर्तमान में राज्य में ऋण प्रावधान की त्रिस्तरीय व्यवस्था है तथा राज्य एवं जिला बैंकों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यकारी सेवा संगठन कार्य कर रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत देश में 63 हजार सेवा संगठनों का कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है. इसमें राज्य के 12 हजार सेवा संस्थान का समावेश है.

प्रक्रिया पूरी होने में 3 से 5 साल का समय लगेगा

- राज्य में 20 हजार से अधिक विभिन्न कार्यकारी सेवा सहकारी सेवा संस्थाएं कार्य कर रहे है.
- केंद्र सरकार के फैसले के पीछे का उद्देश्य इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ इनके माध्यम से विभिन्न सेवाएं और सामान उपलब्ध कराना है. उसी के अनुरूप इन संस्थानों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है.

6-7 चरणों में होगा काम

कम्प्यूटरीकरण के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति की गई है और उसके माध्यम से 6 से 7 चरणों में इन सभी संस्थाएं को कंप्यूटरीकृत करने का काम चल रहा है. इन सभी 12 हजार संस्थानों का कंप्यूटरीकरण अगले 3 से 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा. इन्हें लेकर एक्ट के उपनियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं.